Instances have come to the notice that some passengers attempt to alight at red-lights or at the round-abouts. The commuters are required to follow traffic regulations and to get down at prescribed stops only. The sign-board., have been put at exit-entry points of buses advising commuters not to enter in or alight from a moving bus. The conductors are instruct. ed to be watchful. It is, therefore not considered advisable to make any additional halt point at North Block which is already over-crowded. Most of offices are within walking distance.

दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे

2286. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को भारी घाटे हो रहे हैं और इसके बावजूद निगम को प्राइवेट बसें भाड़े पर लिए जाने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम के मामलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का विचार रखती है ताकि विस्तृत जांच के बाद समिति अपना प्रति-वेदन प्रस्तुत कर सके और उसके आधार पर कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें ; और

(ग) क्या सरकार चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा बरखास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे और इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को मुख्यतः अलाभकर भाड़ा ढांचे और मजदूरी तथा अन्य निवेशों की बढ़ती लागत के कारण भारी घाटा हो रहा है । निगम इस समय प्राइवेट बसों को भाड़े पर नहीं ले रहा है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियुक्त की गई उच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

जहां तक बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किये जाने के प्रस्ताव का संबंध है, दिल्ली परिवहन निगम उच्चतम न्यायालय के 1-3-1989 के आदेशों के अनुसरण में जिन कर्मचारियों द्वारा अपीलें की गई हैं उन अपीलों पर विचार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उनकी जांच करा रहा है ।

Formation of interim Afghan Government ia Pakistan

2287. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY; Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Pakistan based rebels (Afghan Mujahidins) have set up the transitional Government under strong pressure from the Pakistani authorities and secret services of that country and the rebel Afghans ended their shoora in Pakistan on the 24th February, 1989 with an appeal to the world to extend recognition to their 19-member Interim Government stating that their Government would be moved inside Afghanistan within one month; and

(b) if so, what are the details in this regard and what is the assessment and the reaction of the Government of India to the formation of Interim Government by Afghan rebels and their appeal for recognition?

THF. MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Government have seen reports to this effect.

(b) The so-called 'Interim Government' consists mainly of the representatives of